GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 78
ANSWERED ON TUESDAY, JULY 30, 2024

CSR FUND UTILIZATION IN THE COUNTRY

QUESTION

78 Dr. Sasmit Patra:

Will the Minister of Corporate Affairs be pleased to state:

(a) the details of total Corporate Social Responsibility (CSR) Funds utilized in the country since the inception of CSR Fund provision in a year-wise format;

(b) the details of how CSR funds are disbursed and whether there are specific guidelines that the companies and other agencies follow in choosing beneficiaries;

(c) whether there has been any study/committee report on the effectiveness of utilization of such funds in the country; and

(d) whether there has been any cases of violations in CSR Funds spending and if so, the details and the action taken in this regard?

ANSWER

THE MINISTER OF FINANCE
AND CORPORATE AFFAIRS **(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)**

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 78 (3rd POSITION) FOR 30th JULY, 2024 REGARDING CSR FUND UTILIZATION IN THE COUNTRY.

(a): The legal framework for Corporate Social Responsibility (CSR) has been provided under Section 135 of the Companies Act, 2013 ('Act'), Schedule VII of the Act and Companies (CSR Policy) Rules, 2014.

The CSR mandated companies are required to file details of CSR activities annually in the MCA21 registry. All data related to CSR filed by companies in MCA21 registry is available in public domain and can be accessed at www.csr.gov.in. On the basis of the filings made by the companies in the MCA21 registry, the CSR spent by all the companies since inception in a year-wise format is as below:

Sr. No.	Financial Year	Amount (in Cr.)
1.	2014-15	10,065.93
2.	2015-16	14,517.21
3.	2016-17	14,542.51
4.	2017-18	17,098.57
5.	2018-19	20,217.65
6.	2019-20	24,965.82
7.	2020-21	26,210.95
8.	2021-22	26,616.30
9.	2022-23	29,987.92
Grand Total		**184,222.87**

(Data upto 31.03.2024) (Source: Corporate Data Management Cell)

(b): Section 135 of the Act mandates every company having net worth of Rs. 500 crore or more, or turnover of Rs. 1000 crore or more, or net profit of Rs. 5 crore or more during the immediately preceding financial year, to spend at least two per cent of the average net profits of the company made over immediately preceding three financial years. Such expenditure is disbursed by the Companies towards CSR as per the CSR Policy of the Company on activities/areas specified in Schedule VII of the Act.

Schedule VII of the Act indicates the eligible list of activities that can be undertaken by the companies as CSR. Presently it has 12 items which broadly covered the activities relates to Health, sanitation, education, environment, sports, heritage, art and culture, rural development, slum area development, Disaster management, including relief, rehabilitation, and reconstruction activities**,** setting up old age homes, day care centers, measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups etc. The items mentioned in Schedule VII are broad based and can be interpreted liberally.

Contd…2/-

Under the CSR legal framework, it is a Board-driven process. Every CSR mandated company except Companies covered under section 135(9) of the Act shall constitute a CSR Committee. The Committee shall formulate and recommend the CSR policy which indicates the activities inter-alia includes beneficiaries to be undertaken by the company in area or subject specified in Schedule VII. The Board of the company plans, decides, executes and monitors the CSR activities of the company based on the recommendations of its CSR Committee. The Government does not issue any specific direction to the Companies for deciding their CSR Policy or beneficiary.

(c): There is no specific study/committee report on the effectiveness of utilization of CSR funds in the Country. However, to develop a more robust and coherent CSR regulatory and policy framework, and underlying ecosystem the Government had constituted High Level Committee (HLC-2015) in 2015. Subsequently, in the year 2018 another High Level Committee (HLC-2018) was constituted. The HLC-2018 had submitted its report on 07th August, 2019 which is available on the Ministry's website at www.mca.gov.in.

(d): The CSR framework is disclosure based and expenditure on CSR activities is required to be audited by the statutory auditors of the company. Further, Ministry has notified the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, ("CARO, 2020") applicable from FY 2021-22 which requires auditors to state details of any unspent CSR amount. The Board of the company is also required to disclose the CSR Policy implemented by the company in its Board report. Under Rule 4(5) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014 the Board of the company has to satisfy itself that the funds so disbursed have been utilised for the purposes and in the manner as approved by it, and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

Thus, the corporate governance framework along with the existing legal provisions such as mandatory disclosures, accountability of the CSR Committee and the Board, provisions for statutory audit of accounts of the company etc. provide adequate safeguards for CSR activities implemented by the companies. Whenever violation of CSR provisions is reported, action against such non-compliant Companies is initiated as per provisions of the Act after due examination of records and following due process of law.

So far, sanction for prosecution has been accorded in 366 cases. Of these, 175 applications for compounding have been made and 131 cases have been compounded. The non-compliance of CSR provisions has been converted as a civil wrong w. e. f. 22nd January, 2021.

******

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 78
(जिसका उत्तर मंगलवार, 30 जुलाई, 2024 को दिया गया)

देश में सीएसआर निधि का उपयोग

***78. डा. सस्मित पात्रा:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीएसआर निधि प्रावधान के आरंभ होने से लेकर अब तक देश में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सीएसआर निधि का संवितरण कैसे किया जाता है और कया कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं जिनका पालन कंपनियों और अन्य अभिकरणों द्वारा लाभार्थियों को चुनने में किया जाता है;
(ग) क्या देश में ऐसी निधियों के उपयोग की प्रभावशीलता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है/ समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और
(घ) क्या सीएसआर निधि के व्यय में उल्लंघन के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>देश में सीएसआर निधि का उपयोग के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 78 (तीसरा स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।</u>

(क): कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है।

सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित सभी डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, स्थापना के बाद से वर्षवार फार्मेट में सभी कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राशि (करोड़ में)**
1.	2014-15	10,065.93
2.	2015-16	14,517.21
3.	2016-17	14,542.51
4.	2017-18	17,098.57
5.	2018-19	20,217.65
6.	2019-20	24,965.82
7.	2020-21	26,210.95
8.	2021-22	26,616.30
9.	2022-23	29,987.92
कुल योग		**184,222.87**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

(ख): अधिनियम की धारा 135, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा इस प्रकार के व्यय का संवितरण अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों/क्षेत्रों पर सीएसआर के लिए कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार किया जाता है।

अधिनियम की अनुसूची VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को दर्शाती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। इस समय इसमें 12 मदें हैं जिनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, खेल, विरासत, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास, स्लम क्षेत्र विकास, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यकलापों सहित आपदा प्रबंधन**,** वृद्धाश्रमों, डे केयर केन्द्रों की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के उपायों आदि कार्यकलापों को व्यापक रूप से कवर किया गया है। अनुसूची VII में उल्लिखित मदें व्यापक हैं और उनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है।

सीएसआर कानूनी ढांचे के अंतर्गत, यह एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी, अधिनियम की धारा 135(9) के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को छोड़कर, सीएसआर समिति का गठन करेगी। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची-VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा किए जाने वाले लाभार्थी संबंधी कार्यकलापों को इंगित किया गया है। कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, उन पर निर्णय करता है, उनका निष्पादन करता है और उनकी निगरानी करता है। सरकार कंपनियों को उनकी सीएसआर नीति अथवा लाभार्थियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है।

(ग): देश में सीएसआर निधियों के उपयोग की प्रभावकारिता के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन/समिति की रिपोर्ट नहीं है। तथापि, एक अधिक मजबूत और सुसंगत सीएसआर नियामक और नीतिगत ढांचा, और अंतर्निहित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए, सरकार ने 2015 में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-2015) का गठन किया था। इसके पश्चात, वर्ष 2018 में एक और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-2018) का गठन किया गया। एचएलसी-2018 ने 07 अगस्त, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो मंत्रालय की वेबसाइट पर www.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

(घ): सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी बोर्ड को कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना भी अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 (5) के तहत कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधि का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित प्रयोजन के लिए और तौर-तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ**,** कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करके और कानून की सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की जाती है।

अब तक, 366 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इनमें से, प्रशमन के लिए 175 आवेदन किए गए हैं और 131 मामलों का प्रशमन किया गया है। सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन न करने को 22 जनवरी, 2021 से सिविल रॉन्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

*****

DR. SASMIT PATRA: Sir, this is with reference to Item No. (d) of the hon. Minister's reply where specific violations have been referred to. There have been several instances where misuse of Corporate Social Responsibility (CSR) funds has been flagged. It could either emanate from malpractices of use or non-observance of CRS rules. My question is this, what are the steps the Ministry is taking to ensure that such misuse of CSR funds, when found, is prevented and strong punitive measure is taken against the perpetrating companies involved in this and/or the implementing agencies?

SHRI HARSH MALHOTRA: Sir, there are penal provisions for the violation of non-compliance of the transfer of funds, as well as if there is any misappropriation, or the funds are not being used properly, then there are punitive actions for that. And, in that case, for not spending the CSR amount, as well as the non-compliance with the treatment of unspent CSR amount, provisions, as prescribed in Section 135, sub-section (5) and sub-section (6), following penalties are prescribed under Section 135(7). For the companies, if they do not transfer the funds, twice the unspent amount is required to be transferred by the company to any Fund included in the Schedule VII of the Act, as the case may be, or one crore rupees, whichever is less. Secondly, if any officer is at default in this case, then, that officer has to pay one-tenth of the unspent amount, or two lakh rupees, whichever is less.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Sir, my second supplementary is with reference to part (c) of the reply of the hon. Minister. In the reply, the hon. Minister has categorically stated that there is no specific study or committee report on the effectiveness of utilization of CSR funds in the country. It is in the reply. It also states that to ensure a more robust and coherent CSR regulatory and policy framework, the Government instituted a High Level Committee in 2015, which provided its recommendations in 2018. However, my question emanates from the fact that despite five years after the Committee's recommendations have come in, the same have not been implemented. Would the hon. Minister want to specify by when the recommendations of this High Level Committee, instituted to have a robust and coherent CSR regulatory and policy framework, would be implemented? I need an assurance from the hon. Minister if the Ministry is considering it.

SHRI HARSH MALHOTRA: Sir, there are two instances when two High Level Committees have been constituted for this purpose. One was in 2015. The recommendations of that Committee were: (i) the CSR spend data of the company may be placed in the public domain. This has been followed. The second was setting up of the National CSR Awards, which has also been followed. The third was issuance of FAQs by the Ministry on various issues related to CSR. These are there on the website.

There was another High Level Committee constituted after three years to review the CSR data and other implementation issues related to the CSR. According to that, another High Level Committee was constituted in 2018 which also gave its recommendations. The first was that non-compliance of CSR may be made a civil wrong, which is already there. Secondly, companies having CSR amount less than Rs.50 lakhs may be exempted from constituting the CSR Committee, which is being followed. The third was about transfer of unspent CSR Fund to separate designated account created for this purpose, which is also being followed.Then, another recommendation was mandatory registration for implementing agencies. This is a sort of rule.Then, another recommendation was about impact assessment of certain categories of projects by certain class of companies, and development of CSR exchange portal. So, all the suggestions and recommendations of High Level Committees are being followed.

MR. CHAIRMAN: Now, third supplementary, Shri Mukul Balkrishna Wasnik. Third supplementary. Shri Mukul Wasnik.

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने एक स्कीम की घोषणा की, जिसके जरिए यह कहा गया कि 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को internship का अवसर प्रदान किया जाएगा और इन नौजवानों को साल के 60 हजार रुपए, यानी महीने के 5 हजार रुपए मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन अगर हम स्कीम को देखें, तो पता चलता है कि इसके ऊपर कम से कम 60 हजार करोड़ लगेंगे।

MR. CHAIRMAN: Are you on Question No. 78?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: चूँकि वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि 500 चुनी हुई कंपनीज़ की ओर से CSR fund नौजवानों की ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इसकी क्या गाइडलाइंस हैं; कंपनीज़ का चयन कैसे होगा; interns का चयन

कैसे होगा; interns में दलित, आदिवासी, महिलाओं को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा; उसके लिए कोई आयु सीमा रहेगी या नहीं रहेगी? यह माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी तो बजट पास होना बाकी है। माननीय मंत्री जी।

श्री हर्ष मल्होत्रा: सर, हालाँकि आदरणीय सदस्य का प्रश्न इस question के purview में नहीं आता है, पर इसके बारे में मैं सिर्फ इतनी जानकारी दे सकता हूँ ...

MR. CHAIRMAN: The question is very important.

SHRI HARSH MALHOTRA: Yes, Sir. The question is really very important, and, that is why, it is there in the Budget and Rs. 2,000 crore has been assigned for this. Further, the guidelines are being framed. We will let the House and the nation know about it very soon.

MR. CHAIRMAN: It is a complete answer. Now, supplementary number 4, Shri Naresh Bansal.

श्री नरेश बंसल: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि CSR fund से कुछ राशि सांसद आदर्श ग्राम अथवा सांसदों द्वारा अनुमोदित काम के लिए भी तय की जाए, क्या सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, यह सुझाव है।

श्री हर्ष मल्होत्रा: सर, आदरणीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, लेकिन CSR amount, जो stipulated होता है, उसको खर्च करने की एक विधि Companies Act में तय की गई है। अभी उसके according ही इन amounts को खर्च किया जा सकेगा। Schedule VII के अंदर 12 मद हैं, उन मदों में ही इनको खर्च किया जा सकता है। अभी इसके बारे में कोई specific guideline नहीं है। अगर ऐसी कोई गाइडलाइन बनेगी, तो आपको अवगत कराया जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Now, supplementary number 5, Dr. V. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN: Mr. Chairman, Sir, an appropriate study of the expenditure from the CSR funds is very necessary today. Till now, such a study has not been conducted by the Government. Some of the companies are spending the CSR funds for their own promotion, for their own benefit. It should be controlled. That is why, my question is whether the Government has any plan to control such kind of

expenditure of the Companies and whether the Government has any plan to encourage the companies to spend the money for the benefit of the common people. In some areas, this CSR fund is getting only the supporters of the ruling Government. It should be controlled. My question to the Minister is whether the Government has any plans to control such ills in this sector.

श्री हर्ष मल्होत्रा : सर, सम्मानित सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि ये company centric activities हैं और यह बोर्ड की पावर है कि कहाँ खर्च करना है। उसके लिए Companies Act के Schedule VII में जो 12 मद दिए गए हैं, उनको उनमें खर्च करना आवश्यक है और उस financial year में अपना पूरा पैसा खर्च करना आवश्यक है। अगर वे उन बातों से contravene करती हैं, तो उसके लिए penalties का provision है, जो अभी बताया गया है।

MR. CHAIRMAN: Question No.79.